Seventeenth Loksabha

an>

Title:Regarding enhancement in the subsidy amount given under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम) : सभापति जी, धन्यवाद । मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं कि 'प्रधान मंत्री आवास योजना' जो वर्ष 2022 तक थी, उसे वर्ष 2024 तक बढ़ाया गया है । 'प्रधान मंत्री आवास योजना' गरीबों के लिए है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनके लिए है । वैसे भी हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तो गरीबों के लिए मकान देना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन उसमें थोड़ा तफावत है । जो राशि हम 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत शहरों में देते हैं, वह 2 लाख 67 हजार रुपये है और ग्रामीण क्षेत्र में यह राशि 1 लाख 30 हजार रुपये है । मैंने मंत्री जी को लिखा था कि जो यह तफावत है, उसे हटाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरों में एक जैसी राशि के मकान बनें और पक्के मकान बनें, क्योंकि मोदी जी की सरकार है तो सब मुमकिन है । मैं चाहती हूं कि जो हमारा ध्यान गरीबों के ऊपर है, हम उसको और अच्छे तरीके से देखें और उनको फण्ड का आबंटन करें ।

सर, मैं इसमें एक बात और बताना चाहती हूं कि एससी/एसटी के लिए तो आवास भरपूर संख्या में दिए जा रहे हैं, लेकिन करीब 50 परसेंट लोग ओबीसी में हैं । ओबीसी के लोगों का जो कोटा है, उसके लिए राज्य सरकारों को लिखकर उस कोटे में बढ़ोतरी करनी चाहिए । यह आपके माध्यम से मेरी मांग है । हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत के रिजल्ट्स आए हैं, देवेंद्र सरकार और शिंदे सरकार में हमारी संख्या बढ़ी है । हमें वहां पर बहुमत मिला है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी है । मैं चाहती हूं कि इसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए । इसका समय बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जो राशि है, उस राशि को भी बढ़ाया जाए । मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं ।